जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 333 प्रभात उदयपुर, शनिवार 4 अक्टूबर, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

''आई लव मोहम्मद'' अभियान के विरोध या समर्थन का कोई असर नहीं दिख रहा है बिहार के चुनाव में

यह इस बात की पुष्टि करता है कि सदा से ही बिहार की राजनीति में धर्म से ज्यादा जाति असरदार है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। क्या उत्तर प्रदेश का 'आई लव मुहम्मद' अभियान भाजपा द्वारा इस तरह रचा गया था कि बिहार में चुनावी माहौल को सांप्रदायिक बनाया जा सके?

इसी तरह की कई साज़िश की थ्योरी सामने आ रही हैं, खासकर बरेली के मौलाना तौकीर रज़ा ख़ान की गिरफ्तारी और उनके, उनके सहयोगियों व परिवार पर जिला प्रशासन की बुलडोज़र कार्रवाई के बाद।

बिहार की राजनीति पर हिंदुत्व की राजनीति का कोई बड़ा असर अब तक नहीं पड़ा है। यहाँ धर्म से अधिक, जाति ही राजनीतिक पहचान का मुख्य आधार रही है। लेकिन अतीत में कुछ इलाकों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने भाजपा को चुनावी लाभ ज़रूर दिया है।

- जैसा कि विदित है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने गत माह आई लव मोहम्मद अभियान शुरु किया था, जो महाराष्ट्र, उत्तराखंड और गुजरात में भी पहुँचा।
- इसके जवाब में हिन्दुवादी ग्रुप्स ने ''आई लव महादेव'', ''आई लव राम'' पोस्टर वॉर छेड़ा। राजनीति टीकाकारों के अनुसार, इन दोनों अभियानों का ज्यादा असर इसलिये नहीं हुआ, क्योंकि तौक़ीर रज़ा खान को यू.पी. का असदुद्दीन ओवैसी समझा जाता है, जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का कर अपने वक्तव्यों से ध्रुवीकरण करते हैं और इसका फायदा भाजपा को ही मिलता है।
- यह भी कहा जाता है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान बरेली के भाजपा नेता संतोष गंगवार के नज़दीकी हैं और एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने ही जेल से रिहाई के लिए उनकी जमानत की व्यवस्था कराई थी।
- बिहार के सीमांचल क्षेत्र में, जहाँ मुस्लिम मतदाता काफी संख्या में हैं, जरुर ओवैसी की पार्टी को, जो सभी सीटों पर लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि वे मौलाना के पक्ष में अच्छी खासी बयानबाजी कर रहे हैं।

पिछले महीने कानपुर में अल्पसंख्यकों पर पुलिस की कार्रवाई और 'आई लव मुहम्मद' पोस्टर लगाने वालों पर रोक के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। मौलाना तौकीर रज़ा ख़ान ने इनका नेतृत्व किया, जिसके चलते आंदोलन महाराष्ट्र, उत्तराखंड और गुजरात तक फैल गया। इसके जवाब में हिंदू संगठनों ने 'आई लव महादेव', 'आई लव राम' और यहाँ तक कि 'आई लव बुलडोज़र' जैसे पोस्टरों के साथ मुहिम छेड़ दी।

इस पोस्टर राजनीति ने माहौल को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुतिन ने मोदी को साहसी नेता बताया

सोची, 03 अक्टूबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत किसी प्रकार का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।

पुतिन ने काला सागर के तट पर स्थित रूस के सोची शहर में आयोजित वाल्दाई इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब के मंच पर बोलते हुए कहा, ''भारत और चीन अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।'' रूसी राष्ट्रपति का इशारा हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत आयात

- उन्होंने कहा अब भारत पुराना भारत नहीं, अब वो किसी तरह का तिरस्कार बर्दाश्त नहीं करेगा।

शुल्क लगाने और रूस से तेल आयात बंद नहीं करने के कारण 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने के फैसले की ओर था।

रुसी राष्ट्रपति ने मोदी को साहसी नेता बताया और कहा कि, ''भारत अब पुराना भारत नहीं रहा, अब वो किसी तरह का तिरस्कार बर्दाश्त नहीं करेगा।'' पुतिन ने कहा, ''अगर भारत रूस से तेल आयात बंद कर देता है तो इसे बहुत घाटा होगा। पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर जानते

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब तक रूस की सीमा से लगते देश ही ''आतंकित'' थे रूस की आक्रामक कार्यवाही से

पर, अब रूस ने ड्रोन की उड़ानों से व एयर स्पेस उल्लंघन से मध्य यूरोप को भी डराना शुरु कर दिया है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3, अक्टूबर। पश्चिमी यूरोप अब दिन-ब-दिन छद्म युद्ध की मार को तेजी से महसूस कर रहा है, जिससे उसकी जरूरी और अहम सेवाएँ अलग-अलग समयावधि के लिए ठप हो रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस बिगड़ती स्थिति का सामना कैसे किया जाए, इसका कोई स्पष्ट रास्ता नजर नहीं आ रहा।

अब तक ऐसे हमले रूस की सीमा से लगे देशों में हो रहे थे, लेकिन अब गुप्त हमले धीरे-धीरे मध्य यूरोप तक पहुँचने लगे हैं।

कल म्यूनिख हवाईअड्डे को उस समय कई घंटों तक बंद करना पड़ा, जब वहाँ आसपास बड़ी संख्या में ड्रोन देखे गए। उड़ानें बाधित हो गईं और भारी संख्या में यात्री परेशान हुए। सबसे पहले पोलैण्ड में बिना अनुमति उड़ रहे ड्रोन देखे गए थे, जिन्हें पोलिश सेना ने गिरा दिया था। अब ऐसी घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं।

पोलैंड की घटना के बाद, कोपनहेगन हवाईअड्डे को भी ड्रोन की

- सबसे पहले ये ड्रोन की उड़ानें पोलैण्ड में देखी गई थीं। इसके बाद कोपनहेगन, डैनमार्क, एस्टोनिया में भी हुई हैं।
- इन उड़ानों से कई जगह एयरपोर्ट उड़ाने विलंबित हुई हैं। ऐसी घटना दो साल पूर्व हुई थी, जिसमें नॉथ सी में गैस पाइपलाइन को दुर्घटनाग्रस्त किया गया था।
- लंदन की बहुप्रतिष्ठित पत्रिका इकॉनमिस्ट ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सारी आपसी बातचीतों के बावजूद भी अभी तक रूस के खिलाफ कॉमन फ्रंट बनाकर खड़े होने की क्षमता नहीं बनी है। यूरोप को यह भी भय है कि अगर अभी रूस की डराने वाली कार्यवाही नहीं रोकी गई तो रूस की हिम्मत बढ़ती जायेगी। कुछ रूसी भाषी अल्पसंख्यकों की सहायता से वो रूस पर अपना आधिपत्य बढ़ाता जाएगा।

वजह से बंद करना पड़ा। इसके बाद डेनमार्क का बिजनेस एयरपोर्ट भी आसपास ड्रोन उडानों से प्रभावित हुआ। एस्टोनिया में रूसी लड़ाकू विमान उसके हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक उड़ान भरते हुए देखे गए।

ड्रोन के अलावा, यूरोप में जरूरी सेवाओं को बाधित करने वाली घटनाएँ भी बढ़ रही हैं। करीब दो साल पहले उत्तरी सागर में एक बड़ी गैस पाइपलाइन को समुद्र की सतह के नीचे क्षतिग्रस्त पाया गया।

सभी आरोपों की उंगली रूस की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'भारतीय कंपनियां ''क्रोनीइज़्म'' से नहीं मेहनत और इनोवेशन से भी जीत सकती हैं'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत में पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक ही कंपनी के एकाधिकार की कड़ी आलोचना करते हुए यह टिप्पणी की

- डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। पूरी अर्थव्यवस्था पर तीन-चार बड़ी कंपनियों के एकाधिकार की धारणा की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कहा कि दोपहिया वाहन निर्माता बजाज, हीरो और टीवीएस कोलंबिया में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, जो यह साबित करता है कि भारतीय कंपनियां नवाचार (इनोवेशन) के दम पर सफल हो सकती हैं, न कि भाई-भतीजावाद (क्रोनीइज़्म) के जरिए।

दक्षिण अमेरिका के चार देशों के दौरे पर कोलंबिया पहुंचे राहुल गांधी ने 'एक्स' पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की

- दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में हीरो, बजाज और टीवीएस का काम काज देखकर राहुल ने खुशी जताई और एक्स पर एक फोटो भी पोस्ट की, जिसमें वे एक बजाज पल्सर मोटर साइकिल के साथ खड़े दिख रहे हैं। उन्होंने कोलंबिया में भारतीय कंपनियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी।
- कोलंबिया की इआईए युनिवर्सिटी, मैडलीन में विद्यार्थियों के साथ एक संवाद में राहुल ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया और कहा कि पूरे आर्थिक ढांचे को एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंपा जाना चाहिए।

है, जिसमें वे एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल के सामने खड़े हुये हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने 3 प्रतिशत महँगाई भत्ता बढ़ाया

जयपुर, 03 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस माह दीपावली के त्यौहार से पहले राज्य कार्मिकों को महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि का उपहार दिया है। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में 3 प्रतिशत वृद्धि देय होगी।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का

- राज्य कर्मियों और पेंशनरों को 1 जुलाई 25 से बढ़ा हुआ महँगाई भत्ता मिलेगा।

अनुमोदन किया। अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई राहत देय होगी।

इस निर्णय से लगभग 8 लाख कार्मिक एवं 4.40 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।

एयर चीफ मार्शल ने प्रैस कॉन्फ्रैंस में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान को हराया भारत ने

एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने कहा, पूरी दुनिया ने भारतीय वायु सेना की ताकत देखी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3, अक्टूबर। एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रैंस में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा 4 से 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, अमेरिकी एफ-16 और चीनी जेएफ-17 को मार गिराया गया। उन्होंने कहा कि अगस्त में की गई प्रारंभिक टिप्पणी के बाद अब और स्पष्ट विवरण साझा किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि विश्व ने भारतीय वायुसेना की ताकत देखी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी शिविरों और ठिकानों को भी निशाना बनाकर सफलतापूर्वक ध्वस्त किया।

वायुसेना प्रमुख ने बताया, ''हमारे पास यह प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक अवाक्स (एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग सिस्टम) एयरक्राफ्ट और 4 से 5 फाइटर जेट्स को हवा में ही नष्ट किया गया। कुल मिलाकर 6 पाकिस्तानी विमान हमारी कार्रवाई में तबाह हुए।''

इसके अलावा, भारतीय मिसाइल

- उन्होंने बताया, हमारी सेना ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों के साथ एक ''अर्ली वॉर्निंग एण्ड कंट्रोल प्लेन'' नष्ट किया था और यही नहीं अमेरिका में बने सी-130 विमान, जिसे ''हरक्युलिस'' कहा जाता है, को भी नष्ट किया है।
- सिंह ने बताया, ''अर्ली वॉर्निंग एण्ड कंट्रोल प्लेन'' को 300 किलोमीटर दूर से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया, जो अब तक का सबसे लंबी दूरी का निशाना है।
- उन्होंने कहा, हमारे हर हमले के हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। पर, पाकिस्तान जो भारतीय राफेल गिराने के जो दावे कर रहा है, वह सिर्फ झूठा प्रचार है, जो वह अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए कर रहा है।

हमलों ने पाकिस्तानी रडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सैंटर, रनवे, हैंगर और अन्य सैन्य ढांचों को भी निशाना बनाकर निष्क्रिय कर दिया।

उन्होंने यह भी बताया कि हो सकता है कि सी-130 क्लास का एक अमेरिकी सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान, जिसे ''हर्क्यूलिस'' कहा जाता है, वह भी निशाना बना हो।

उन्होंने कहा, ''पाकिस्तान के नुकसान की बात करें तो हमने उनके कई एयरफील्ड्स और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इसमें चार स्थानों पर रडार, दो स्थानों पर कमांड एंड कंट्रोल सैंटर, और दो रनवे क्षतिग्रस्त हुए। तीन विभिन्न एयरबेस पर तीन हैंगर भी नष्ट हुए,'' उन्होंने कहा।

एयर चीफ ने बताया कि एक एईडब्ल्यु एण्ड सी या इलैक्ट्रॉनिक इन्टैलिजैंस विमान को 300 किलोमीटर से अधिक दूरी से निशाना बनाकर मार गिराया गया, जो अब तक का सबसे लंबी दूरी का सतह से हवा में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोनम वांगचुक की रिहाई के लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नयी दिल्ली, 03 अक्टूबर। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने उनकी रिहाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

अंगमो ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका

- वांगचुक की पत्नी की याचिका पर दशहरा की छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी।

गुरुवार को दायर कर अपने पति की गिरफ्तारी को अवैध बताया है।

उन्होंने अपनी याचिका में अपने पति पर एनएसए लगाने पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उनकी ''गिरफ्तारी अवैध और नियमों का उल्लंघन है।'' उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के बाद उनके पति से कोई संपर्क नहीं हो पाया।

गौरतलब है कि वांगचुक राजस्थान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका के शटडाउन का असर धीरे-धीरे सरकारी कर्मचारियों और जनता को महसूस होने लगा

केन्द्रीय सरकार के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को अगले सप्ताह पे चैक नहीं मिलेगा और उन्हें अपनी बचत भुनाकर रोज़मर्रा का खर्चा चलाना पड़ेगा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। वॉशिंगटन में बजट पर गतिरोध अब एक पूर्ण अमेरिकी सरकारी शटडाउन में तब्दील हो गया है, जिससे लाखों अमेरिकियों को वित्तीय अनिश्चितता, ठप्प सेवाओं और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता का सामना करना पड़ रहा है।

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और कांग्रेस के बीच वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी संघीय फंडिंग की अवधि समाप्त हो गई है। सांसद एक अस्थायी फंडिंग प्रस्ताव पर सहमति नहीं बना सके, जिससे सरकारी एजेंसियों को अपने कामकाज रोकने या सीमित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

करीब साढ़े सात लाख संघीय कर्मचारियों के लिए यह शटडाउन अनिवार्य अवकाश (फर्लो) है, जिसका अर्थ है कि, जब तक कोई फंडिंग बिल पास नहीं होता, तब तक बिना वेतन घर बैठना पड़ेगा। जरुरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी, जैसे सेना के जवान, बॉर्डर एजेंट और एयरपोर्ट कंट्रोलर, को बिना वेतन काम करना होगा। अगले सप्ताह तक, कई कर्मचारियों को अपना पहला वेतन नहीं मिल पाएगा, जिससे परिवारों को अपनी बचत को खर्च करना पड़ेगा या कर्ज़ लेना पड़ सकता है।

इस शटडाउन के प्रभाव पहले ही दिखने लगे हैं। हवाई यातायात यूनियनों ने स्टाफ की कमी को लेकर चेतावनी दी है, जिससे उड़ानों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। राष्ट्रीय उद्यान, संग्रहालय और कई सार्वजनिक सेवाएं- जैसे पासपोर्ट कार्यालय और छोटे व्यवसायों के लिए लोन डेस्क आदि अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। सेवानिवृत्त नागरिकों, पूर्व सैनिकों और ग्रामीण इलाकों में सरकारी सहायता पर निर्भर परिवारों के लिए यह शटडाउन पहले से ही कठिन आर्थिक स्थिति में मुश्किले बढ़ा रहा है।

इस बार का संकट पहले के शटडाउन की तुलना में ज्यादा गंभीर है, क्योंकि वाइट हाउस की ओर से स्थायी

- जब तक बजट प्रस्ताव सीनेट से पारित नहीं होता, बिना तनख्वाह के छुट्टी पर जाने को मजबूर होना पड़ेगा। रिटायर्ड कर्मचारी, पूर्व सैनिक व ग्रामीण परिवार, जो सरकारी मदद पर निर्भर हैं, उनके जीवन में आर्थिक तनाव और बढ़ जायेगा।
- साधारण नागरिक के लिए नैशनल पार्क, म्यूज़ियम व अन्य पब्लिक सेवाएँ, यहाँ तक कि एयरपोर्ट व हवाई सेवा भी सुरक्षाकर्मियों के अभाव में अस्त-व्यस्त होनी शुरु हो गई हैं।

छंटनी के संकेत दिए जा रहे हैं। प्रेस सचिव कैसेलीन लेविट ने कहा कि एजेंसियां अब यह समीक्षा कर रही हैं कि ''कहां-कहां छंटनी सन्निकट है,'' जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि कई कर्मचारी अब अपनी नौकरियों पर वापस नहीं लौट पाएंगे।

सरकार इस फंडिंग अवरोध का इस्तेमाल अपने खर्च प्राथमिकताओं नया रुप देने के लिए कर रही है। ऊर्जा विभाग ने घोषणा की है कि वह स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं को बंद कर रहा है- खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा शासित राज्यों में। वहीं, परिवहन विभाग ने न्यूयॉर्क के लिए 18 अरब के इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स को फ्रीज कर दिया है। आलोचकों ने इन फैसलों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा है।

यह गतिरोध हैल्थकेयर फंडिंग सीनेट डेमोक्रेट्स कम आय वाले परिवारों के लिए सब्सिडी बढ़ाना चाहते हैं, जबकि रिपब्लिकन किसी भी नए खर्च का विरोध कर रहे हैं और डेमोक्रेट्स पर आरोप लगा रहे हैं कि वे यह पैसा अवैध प्रवासियों को देने की कोशिश कर रहे हैं - जिसे डेमोक्रेट्स ने सिरे से नकारा है। बिना द्विदलीय समर्थन के, सीनेट 60 वोटों की आवश्यक संख्या जुटा नहीं पा रही है, जिससे कोई भी अल्पकालिक समाधान भी असंभव हो गया है।

आम अमेरिकी नागरिकों के लिए, यह शटडाउन वॉशिंगटन की राजनीतिक विफलता की एक कड़वी याद दिलाता है। रोज़मर्रा की सुविधाएं - जैसे परमिट रिन्यू कराना या राष्ट्रीय उद्यानों की सैर - अब बंद हैं। जिन संघीय कर्मचारियों की ज़िंदगी महीने की तनख्वाह पर टिकी है, उनके लिए यह स्थिति बेहद कठिन है।

वॉशिंगटन में घूमने आए एक सेवानिवृत्त व्यक्ति ने कहा, जो आज कई अमेरिकियों की साझा भावना बन गई है।

''समझौता किया जाता है। रास्ते निकाले जाते हैं। सबको थोड़ा-थोड़ा पीछे हटना पड़ता है।''

जहां रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वे नीति-निर्धारण के लिए सरकार को बंधक बना रहे हैं, वहीं डेमोक्रेट्स जवाब दे रहे हैं कि ट्रंप की सार्वजनिक सेवाओं में की जा रही आक्रामक कटौतियां समाजिक सुरक्षा तंत्र को खतरे में डाल रही हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'दो साल तक के बच्चों के कफ सिरप ना दें'

नयी दिल्ली, 03 अक्टूबर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत की रिपोर्टों को देखते हुए, केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने दो

- केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राजस्थान व मध्यप्रदेश में कफ सिरप पीने से हुई छोटे बच्चों की मौतों के मद्देनज़र यह निर्देश दिया।

साल तक के बच्चों को कफ सिरप न देने का निर्देश दिया है।

महानिदेशालय की ओर से शुक्रवार को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवा निदेशकों को जारी परामर्श में कहा है कि बच्चों में आम तौर से होने वाली खांसी अपने-आप ठीक हो जाती है और किसी दवाई की जरूरत नहीं होती। उसने कहा है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को सर्दी और खांसी की दवा नहीं दी जानी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)